भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2701

16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

इंटरसिटी ई-बस फ्लीट का विद्युतीकरण

2701 **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अंतर-शहर बस बेड़ों के विद्युतीकरण हेतु राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है अथवा इस पर विचार कर रही है;

(ख) अंतर-शहरी मार्गों पर परिचालित इलेक्ट्रिक बसों की वर्तमान हिस्सेदारी और कुल संख्या कितनी है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर-शहर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने से जुड़े पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अंतर-शहर ई-बसों की खरीद या तैनाती को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रासंगिक योजनाओं के अंतर्गत शुरु की गई पहलों की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर चार्जिंग उपलब्धता सहित बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपायों का प्रस्ताव किया है या उन्हें कार्यान्वित किया है;

(च) क्या मुंबई-गोवा राजमार्ग और समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे जैसे अतिरिक्त गलियारों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है और;

(छ) क्या सरकार इंटरसिटी ई-बस परिनियोजन के लिए अग्रिम परियोजना लागत को कम करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसे वैकल्पिक खरीद और वित्तपोषण मॉडल पर विचार कर रही है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): इस तरह का डेटा एमएचआई में केंद्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

(ग): एमएचआई द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(घ): फेम-II इंडिया स्कीम के द्वितीय चरण के तहत, एमएचआई ने अंतर-शहरी प्रचालन के लिए 450 ई-बसों को मंजूरी दी थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू)	आवंटित ई-बसों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी)	50
2	गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी)	50
3	कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी)	50
4	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी)	150
5	कदंबा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केटीसीएल)	150

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 29.09.2024 को अधिसूचित पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आरंभ में, इस स्कीम का लक्ष्य 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों को लक्षित करना है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे शामिल हैं। अंतर-शहर/अंतर-राज्य ई-बसों को शुरू करने पर भी राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके विचार किया जाएगा।

(ङ): प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम के तहत राजमार्गों सहित अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(च) और (छ): भारी उद्योग मंत्रालय में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****